(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त परियोजना के क्रियान्वयन से सरकार के पर्यावरणीय कार्यक्रम पर प्रतिकूल अंतर पड़ेगा ;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ,

(घ) क्या यह सच है कि यदि उपर्युक्त परियोजना को क्रियान्वित कर दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अनेकों वन लुप्त हो जायेंगे ; और

(ङ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वनों की रक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल): (क) से (ङ) नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर और सरदार सरोवर दोनों परियोजनाओं को अनुमोदित किए जाने के प्रश्न पर सभी पर्यावरणीय प्रभावों के संदर्भ में विचार किया जा रहा है । दोनों परियोजनाओं से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में कुल 54,076 हेक्टेयर वनों की क्षति होगी । अनुमोदन के प्रश्न पर विचार करते समय उन कदमों को भी ध्यान में रखा जाएगा जिनको वनों की सुरक्षा करने अथवा प्रतिपूरक वनरोपण करने के लिए उठाए जाने की जरूरत है ।

Welfare schemes for child labour engaged in glass works

*18. SHRIMATI RATAN KUMARI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any welfare scheme, including medical and educational facilities for workers especially the child labour, engaged in glass works in Firozabad, U.P.;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government have taken any steps for fixation of minimum wages in the above industry;

(d) if so, what are the details thereof; and

(e) what steps have been taken or are proposed to be taken by Government for strict implementation of labour laws in the above industry?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) A scheme for benefiting child workers employed in the glass industry in Firozabad is being finalized by the State Government of Uttar Pradesh.

(c) Yes. Sir; the State Government which is the appropriate Government for fixing the minimum wages in the glass industry has fixed such minimum wages.

(b) The minimum wages in the glass industry in Uttar Pradesh fixed by the State Government are as follows:

Unskilled workers ..... per day Rs. 18.95.

Semi-skilled workers ..... per day Rs. 19.95.

Skilled workers ..... per day Rs. 20.95.

These wage rates include variable D.A.

(e) The State Government has been addressed from time to time for strict enforcement of labour laws relating to child workers, and prosecutoins are launched by the State Government as and when violations of laws are detected.

राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

*19. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि किसी भी भाषा के विकास और प्रगामी प्रयोग के लिए टेलेक्स, टेलीप्रिंटर, कम्प्यूटर आदि जैसी यांत्रिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है और सरकार ने किसी भी मंत्रालय को अभी तक ये यांत्रिक सुविधायें देवनागरी में उपलब्ध नहीं कराई है ,